



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2017/आषाढ़ 30, 1939

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2017/ ASADHA 30, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

प्रकरण सं. ओ आई-33/2017

(मूल जांच)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और मलेशिया के मूल के अथवा वहां से "सोलर सैल, आंशिक रूप से जोड़े गए अथवा मॉड्यूल में पूर्णतः अथवा पैनल अथवा ग्लास पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त रूप में," के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/30/2017-डीजीएडी.—भारतीय सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष पाटनरोधी जांच आरंभ करने और चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और मलेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैल के आयातों के विषय में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और चूंकि, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि संबद्ध वस्तुओं, संबद्ध देशों में उत्पादित या निर्यातित, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रमाण पाटनरोधी जांच को उचित ठहराने के लिए विद्यमान हैं, अतः प्राधिकारी एतद्वारा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 की शर्तों के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में तथाकथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि

लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, के लिए घरेलू उद्योग को तथाकथित पाटन और हो रही परिणामी क्षति के संबंध में जांच शुरू करते हैं।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सैल है, (चाहे वे आंशिक रूप से जोड़े गए हों या नहीं अथवा मॉड्यूल में पूरी तरह से हों अथवा पैनल हों अथवा ग्लास में हों अथवा किसी अन्य रूप में हों) संक्षिप्तता के लिए यहां उसे संबद्ध सामान कहा गया है।

4. सोलर सैल एक ठोस अवस्था वाला विद्युत उपकरण है जो सूर्य की रोशनी को सीधे ही फोटोवोल्टायिक प्रभाव से बिजली में बदलता है। सोलर सैलों का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए उन्हें पैनलों में अथवा मॉड्यूल में अथवा ग्लास के रूप में अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है। सोलर पैनल/मॉड्यूल एक पैकेज है जो सोलर सैलों की जुड़ा हुआ संयोजन है। पतली फिल्म में भी पैनल/मॉड्यूल हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सैल, मॉड्यूल और पतली फिल्में आती हैं।

5. सोलर सैल बाजार क्षेत्र में फोटोवोल्टायिक सैलों के रूप में भी जाने जाते हैं। फोटोवोल्टायिक प्रौद्योगिकी से सूर्य की रोशनी को विद्युत में सीधे ही परिवर्तित किया जाता है और फोटोवोल्टायिक प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए सोलर सैलों/मॉड्यूलों अथवा पैनलों का उत्पादन किया जाता है और उसका प्रयोग बिजली के उत्पादन के लिए सौर विद्युत संयंत्रों में प्रमुख रूप से किया जाता है। विद्युत में सौर ऊर्जा के परिवर्तन में अर्धचालक युक्ति में होता है जिसे सोलर सैल के रूप में भी जाना जाता है। एक सोलर सैल वह इकाई है जो वॉट के रूप में विद्युत कुछ विद्युत ऊर्जा की मात्रा देती है और विशेष मात्रा में वॉट प्राप्त करने के लिए कई सोलर सैलों को साथ-साथ जोड़ा जाता है ताकि सोलर पैनल बन सके, इसे पी वी मॉड्यूल भी कहते हैं। सौर विद्युत के व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए सोलर पैनलों को एक सोलर अरे में साथ-साथ जोड़ा जाता है।

6. संबद्ध उत्पाद जैसाकि प्रस्तुत किया गया है, के विनिर्माण के लिए दो प्रमुख प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। वह हैं (1) क्रिस्टलीन सिलिकॉन (सी-एसआई) आधारित सोलर सैल प्रौद्योगिकी जिसे जल आधारित प्रौद्योगिकी भी जाना जाता है और (2) पतली फिल्म प्रौद्योगिकी में एमोरफस सिलिकॉन, कैडमियम टेलोरियम (सीडीटीई) अथवा कॉपर इंडियम गैलियम सिलेनियम को अर्धचालक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी-एसआई प्रौद्योगिकी और पतली फिल्म प्रौद्योगिकी दोनों के सोलर सैलों का भारत में आयात किया गया है। विचाराधीन उत्पाद में दोनों प्रौद्योगिकियों अर्थात् क्रिस्टलीन प्रौद्योगिकी और पतली फिल्म प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित सोलर सैल शामिल हैं।

7. विचाराधीन उत्पाद दायर किए गए आवेदन में शामिल है और इस जांच में वर्तमान में उप शीर्ष 85414011 के तहत क्षतिकारक प्रशुल्क प्रणाली ("एचएसएन") में वर्गीकृत है। जो दोनों प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विनिर्मित सोलर सैलों/मॉड्यूलों के लिए समान है।

8. आवेदक सोलर सैलों/मॉड्यूलों का विनिर्माण याचिका में दिए गए अनुसार सी-एसआई प्रौद्योगिकी/क्रिस्टलीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके करते हैं। याचिकाकर्ता पतली फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सोलर सैलों का उत्पादन नहीं करते। तथापि, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, इन दोनों आयातित प्रौद्योगिकियों के संबद्ध सामानों तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित सामानों के बीच वास्तविक अंतर नहीं है क्योंकि इन दोनों प्रौद्योगिकियों की संबद्ध वस्तुएं समान उत्पाद हैं और समान अंतिम प्रयोग अर्थात् सौर ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू रूप से विनिर्मित संबद्ध सामान आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" हैं।

ख. समान वस्तु

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सामान के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोलर सैल और मॉड्यूल तथा संबद्ध देशों से निर्यातित यही सामान अनिवार्य उत्पाद की विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि दोनों सामान तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए उन्हें

नियमावली के तहत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजन से याचिकाकर्ता द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से निर्यात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" के रूप में मानते हैं।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह याचिका इंडियन सोलर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) (जिन्हें यहां बाद में याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा मै. इंडो सोलर लिमिटेड, मै. वैबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, मै. जुपीटर सोलर पावर लिमिटेड और मै. जुपीटर इंटरनेशनल लिमिटेड—संबद्ध सामानों के उत्पादकों की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। भारत में संबद्ध सामानों के शेष ज्ञात उत्पादक याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे अनुसार संबद्ध सामानों का स्वयं आयात कर रहे हैं।

11. याचिकाकर्ता ने घोषणा की है कि यह संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। चूंकि आवेदक का घरेलू उत्पादन का बहुत बड़ा अनुपात है अतः वह नियम 2(ख) के तहत शर्तों के अभिप्राय के भीतर घरेलू उद्योग है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और मलेशिया (जिन्हें "संबद्ध देश" कहा गया है) हैं।

ङ. सामान्य मूल्य

13. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

आवेदकों ने संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विधिवत समायोजित कर किए जाने का दावा किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया इस जांच की शुरुआत के प्रयोजन से आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्मित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

तथापि, प्रश्नावली का उत्तर देते समय उत्पादकों/निर्यातकों को विनिर्माण से संबंधित मौजूदा बाजार स्थिति, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध सामान की बिक्री तथा भारत तथा अन्य देशों को निर्यात में बिक्री दर्शानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उत्पादक/निर्यातक स्पष्ट करें तथा निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदान करें।

- (क) कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्री और निवेश सहित कीमत, लागत, इनपुट के संबंध में निर्णय महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के बिना हैं और क्या प्रमुख इनपुट की लागत बाजार मूल्य में पर्याप्त रूप से दर्शायी गई है।
- (ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पर किसी विकृति के कारण प्रभाव नहीं पड़ता।
- (ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालियापन तथा संपत्ति संबंधी कानून के अधीन हैं जो कानूनी सुनिश्चितता की गारंटी देते हैं और फर्म के प्रचालन के लिए स्थिरता बताते हैं।
- (घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

14. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक पटल पर विश्वसनीय सूचना उपलब्ध न होने के कारण संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का आकलन कच्ची सामग्री की विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जब कभी वे भारत में प्रमुख कच्ची सामग्री की आयात कीमतों के आधार पर उपलब्ध हों तथा घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत मालमू हो, जोकि बिक्री, सामान्य एवं प्रशासन व्यय तथा पर्याप्त लाभ के निमित्त विधिवत रूप से समायोजित की गई हो।

च. निर्यात कीमत

15. याचिकाकर्ता ने इम्पैक्स स्टैटिस्टिक सर्विसेज के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध सामानों के लिए निर्यात कीमत का दावा किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े के खर्च, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों को कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

छ. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य की तुलना कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत से की गई है। इसका प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों का निर्यात मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत से अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध सामान संबद्ध देशों से निर्यात द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, आकलित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

17. याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पूर्ण रूप से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में तथाकथित पाटन और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में, कीमत न्यूनीकरण, कम कीमत पर बिक्री और परिणामस्वरूप लाभ के संदर्भ में प्रतिकूल प्रभाव, लगाई गई पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह के रूप में हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। वास्तविक क्षति के दावे के अलावा याचिकाकर्ता ने निकट भविष्य में उनके निष्पादन पर पाटित आयातों से पैदा हो रहे खतरे का भी दावा किया है और इस संबंध में अनुरोध किया है।

पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

18. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2017 (15 माह) है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 13 से मार्च, 14, अप्रैल, 14 से मार्च, 15, अप्रैल 15 से मार्च, 16 तक तथा जांच की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद के साथ संबद्ध भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में व निर्धारित तरीके से प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत कर सकें और अपने विचार नीचे दिए गए पतों पर प्राधिकारी को भेज सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र और तरीके में नीचे दी गई समय सीमा के भीतर भेज सकता है।

ट. समय-सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई जानकारी और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से अनधिक ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी तक पहुंच सके। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज करा सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे तत्कालीन मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और अपनी प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों को और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन के संबंध में अपनी टिप्पणियों को इस जांच के आरंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर दायर करें।

ठ. अगोपनीयता आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. यदि प्रश्नावली के प्रत्युत्तर/प्रस्तुतियों के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सैटों में प्रस्तुत करना होगा (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) और (ख) अगोपनीय के रूप में चिह्नित अन्य सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित)। आपूर्ति की गई सारी जानकारी से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी भाग पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करानी होंगी।

25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचनाप्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ढ. असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

Case No. OI- 33/2017

(Original Investigation)

Subject: Initiation of Antidumping investigation concerning imports of “Solar Cells whether or not assembled partially or fully in modules or Panels or on glass or some other suitable substrates” originating in or exported from China PR, Taiwan and Malaysia.

F. No. 6/30/2017-DGAD: Indian Solar Manufactures Association (hereinafter referred to as the petitioner) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duties concerning imports of ‘Solar Cells whether or not assembled in modules or Panels or on glass or some other suitable substrates’ (hereinafter also referred to as subject goods), originating in or exported from China PR, Taiwan and Malaysia (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, on finding prima facie that evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and a causal link between the said dumping and injury exists to justify an initiation of anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry concerning imports of the subject goods from subject countries in terms of Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and injury to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

a. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is ‘Solar Cells whether or not assembled partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates’ (hereinafter referred to as Subject goods for the sake of brevity) originating in or exported from China PR, Taiwan and Malaysia.

4. Solar cell is a solid state electrical device that converts sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. To make the practical use of solar cells, the same is placed in panels or modules or on glass or some other suitable substrates. A solar panel/module is a packaged, connected assembly of solar cells. Thin films are also panels/modules. Scope of Product Under Consideration covers cells, modules and thin films.

5. Solar cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic technology enables direct conversion of sun light into electricity and to make the practical use of photovoltaic technology, solar cells/modules or panels are produced and the same is predominantly used in solar power plants to generate electricity. Solar energy conversion into electricity takes place in a semiconductor device which is known as a solar cell. A single solar cell is a unit that delivers a certain amount of electrical power in terms watt and in order to achieve a particular amount of wattage, number of solar cells have to be connected together to form a solar panel, also called as PV module. For large-scale generations of solar electricity, the solar panels are connected together into a solar array.

6. There are two major technologies available for manufacturing of subject product as submitted. They are: (1) Crystalline Silicon (c-Si) based solar cell technology which is also known as wafer based technology and (2) Thin film Technology. The thin film technology may also use, Amorphous Silicon, Cadmium Tellurium (CdTe) or Copper Indium Gallium Selenide as semiconductor materials. Solar cells of both c-Si Technology and Thin Film Technology have been imported into India. The product under consideration (PUC) includes solar cells produced through both the technologies i.e. crystalline technology and thin film technology.

7. Product under consideration covered in the application filed and in this investigation is currently classified in the Harmonized Tariff System (“HSN”) under subheading 8541 4011 which is common for Solar cells/modules manufactured through both the technologies.

8. The applicants manufacture solar cells/modules using c-Si Technology/crystalline technology as provided in the petition. The petitioners do not produce solar cells using Thin Film Technology. However, as claimed by the petitioner there is no material difference between subject goods of both these technologies imported and that manufactured by the applicants as the subject goods of both these technologies are like product and are used for same end use i.e for production of electricity from solar energy. The petitioner has claimed that the domestically manufactured subject goods are 'like article' to the imported PUC.

b. Like Article

9. The petitioner has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. As submitted by the petitioner, Solar Cells and Modules produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The petitioner has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the petitioner in India as 'Like Article' to the PUC being imported from the subject countries

c. Domestic Industry & Standing

10. The petition is filed by Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) [hereinafter referred as the 'Petitioner'] on behalf of M/s Indosolar Limited, M/s Websol Energy Systems Limited, M/s Jupiter Solar Power Limited and M/s Jupiter International Limited—producers of subject goods. Petitioner have provided all the necessary information in the form and manner prescribed by the Designated Authority. Rest of the known producers of the subject goods in India are themselves importing the subject goods as claimed by the petitioner.

11. The petitioner has declared that it is not related either to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India. Since the applicant commands a major proportion of the domestic production, it constitutes the domestic industry, within the meaning of the terms under Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the AD Rules.

d. Subject Countries

12. The countries involved in the present investigation are China PR, Taiwan and Malaysia (referred to as the "subject countries").

e. Normal Value

13. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy country and its normal value be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

The applicants have claimed normal value for subject countries on the basis of cost of production in India, duly adjusted. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

However, while submitting the questionnaire response producers/exporters may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
- b) Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
- c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

14. The petitioners have submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries, the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production taking into account prevailing international prices of raw materials,

wherever available based on import prices of major raw material into India and conversion costs of the domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

f. Export Price

15. The petitioner has claimed export price for the subject goods on the basis of Impex Statistic Services data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at net export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence with regard to the export price claimed by the petitioner.

g. Dumping Margin

16. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margin so estimated is above de minimis levels and is significant.

h. Injury and Causal Link

17. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed and cash flow of the domestic industry. Apart from claims of material injury, the petitioner has also claimed threat being created by the dumped imports on their performance in the imminent future and made submission to this effect.

There is prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

i. Period of Investigation (POI)

18. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st April-2016 to 30th June-2017(15 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16 and the period of investigation has been considered.

j. Submission of information

19. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce,
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.**

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

k. Time limit

21. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

I. Submission of Information on Non-Confidential basis

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

25. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

m. Inspection of Public File

29. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

n. Non-cooperation

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority